देश की आत्मा का व्यापार

डॉ. अशोक जैनर, लंदन से

शिक्षा किसी भी देश की आत्मा होती है। किसी भी परिवार व देश का भविष्य उसकी शिक्षा के गुणवत्ता से नापा जाता है। जो देश शिक्षा में निवेश नहीं कर पाता वह देश अपने नागरिकों के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल देता है। हमारे देश में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के नाम पर इसे निजी लोगों के लिए व्यापार बना दिया है। यदि शिक्षा व्यापार का रूप लेने लगे तब समझ लेना चाहिए कि देश शिक्षा को केवल अमीरों तक ही सीमित रखना चाहती है। यदि शिक्षा केवल अमीरों के घर तक सिमट कर रह जायेगी तब उस देश के अच्छे दिन कैसे आयेंगे? तब 70 प्रतिशत गांव में रहने वाली जनता का क्या होगा?

आज सरकारी स्कूलों का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूल केवल उन गरीबों के लिए अपना मन बहलाने के लिए रह गए जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों का दरवाजा नहीं दिखा सकते हैं। ये स्कूल हर रोज बरसाती छतरी की तरह बढ़ते जा रहे हैं। निजी स्कूल अच्छे-अच्छे भवन, एयरकंडीशन भवन, अच्छे-अच्छे नाम जैसे ऑक्सफोर्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रीज स्कूल आदि। इन स्कूलों में प्रवेश करके लगता है जैसे ये स्कूल न होकर एक अच्छा होटल हो। जितने अच्छे स्कूल के भवन होंगे उतनी ही अधिक स्कूल की फीस होगी।

जैसे-जैसे शिक्षा का व्यापार बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे व्यापार बढ़ाने के नये-नये तरीके निकाले जा रहे हैं। बच्चों को भवन शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, किताबों तथा ड्रेस के नाम पर अधिक पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसके साथ-साथ शैक्षिक दौर के नाम पर बड़े-बड़े शहर कई बार नासा के नाम पर अमेरिका तक जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। सभी निजी स्कूल पैसा कमाने और व्यापार बढ़ाने में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। निजी स्कूलों की कड़ी बनती जा रही है। एक स्कूल से शुरू करके अगले साल उसको दो स्कूल बन जाते हैं। इससे अच्छा व्यापार क्या होगा जिस व्यापार में कोई घाटा ना हो, जिस व्यापार में मुनाफा स्कूल मालिकों के हाथ में है जब चाहे तब फीस बढ़ा दे। शिक्षा का व्यापार जितनी तेजी से पिछले दो दशकों में बढ़ा उतनी ही शिक्षा गरीबों से दूर, गांव वालों से दूर होती चली गयी। अब तो लगता है आने वाले समय में शिक्षा केवल उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के परिवारों तक ही सीमित होकर रह जायेगी। गरीब गांव वाले शिक्षा के नाम पर केवल सरकारी स्कूलों में अपना नाम दर्ज कर सकेंगे। एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टी सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नाम पर राजनीति की रोटियां सेक रही है। जनता उनके पीछे अपना भविष्य देखना चाहती है। यहां पर जनता यह नहीं समझ पाती है की भविष्य शिक्षा से सुधरता है, शिक्षा की प्रणाली से सुधरता है, शिक्षा कि गुणवत्ता से सुधरता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण अच्छी शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता। यहीं पर जनता की आंखों में आरक्षण एक प्रकार की धूल झोकने के समान है।

2016 के आकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लगभग 40 प्रतिशत बच्चे अब निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जबकी गांवों के लगभग 20 प्रतिशत बच्चे ही निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे सरकारी स्कूलों की संख्या भी कम होती जा रही है। इसके विपरीत निजी स्कूलों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत जल्द ही देश के लगभग 50 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे। यह किसी भी देश के लिए एक खतरे की घन्टी के समान है। जैसे ही निजी स्कूलों की भागीदारी 50 प्रतिशत से ज्यादा होगी वैसे-वैसे अन्दर ही अन्दर एक प्रकार की ज्वालामुखी का जन्म होगा। यह ज्वालामुखी एक दिन देश में विस्फोटक का रूप लेने में सफल होगी। देश की शिक्षा प्रणाली देश को गरीबों व अमीरों में विभाजित कर देगी। जिस प्रकार आज सरकार स्वास्थ्य में निजी भागीदारी के कारण गरीबों के लिए स्वास्थ्य जीवन योजना ला रही है। उसी प्रकार एक दिन सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में सब्सिडी या फिर शिक्षा के लिए भी शिक्षा की जीवन बीमा की तरह योजना लानी पड़ेगी। इसके साथ-साथ एक समय ऐसा आएगा जब शिक्षा के लिए भी आरक्षण की आवाज उठने लगेगी क्योंकि आम आदमी का सरकारी स्कूलों से विश्वास पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगा तथा निजी स्कूलों की शिक्षा उनके पहुंच से बाहर हो जायेगी। इसी प्रकार अन्दर की व्याकुलता ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलेगी। तब फिर राजनीतिक पार्टी इसका अपने-अपने तरीके से उपयोग करना चाहेगी। दुनिया के किसी भी देश को शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी भागीदारी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। निजी भागीदारी व्यापार को बढ़ावा देती है तथा देश की आत्मा से कभी भी व्यापार नहीं किया जा सकता। देश की आत्मा की रक्षा केवल व केवल आम आदमी को अच्छी व मुफ्त शिक्षा से ही की जा सकती है। मैं देश की सरकार से अपना व आम आदमी के दर्द को रखते हुए अनुरोध करता हूं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए तुरन्त एक शिक्षा नीति लाये। जिसके द्व ारा सरकारी व निजी दोनों को आम आदमी के लिए सस्ती व अच्छी शिक्षा देने का प्रावधान हो। निजी स्कूलों की फीस तथा गुणवत्ता पर सरकार एक आयोग बनाए। यह आयोग लगातार सरकारी व निजी स्कूलों पर अंकुश लगाये तथा निर्धारित करे कि आम आदमी के दरवाजे तक अच्छी शिक्षा तथा सस्ती शिक्षा पहुंच सके। यह आयोग निजी स्कूलों को अपनी मनमानी ना करने दे। ऐसा करने से आम आदमी का भविष्य तथा देश का भविष्य उज्ज्वल होगा।